

संक्षिप्त समाचार

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री
माणिक साहा कर सकते
हैं मंत्रिमंडल विस्तार

अगरतला, एजेंसी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा बुधवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं।

आधिकारिक सूची ने यह जनकारी दी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पर लौटने के बाद साहा मुख्यमंत्री बने। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले टिप्पणी मोथा पार्टी (टीएमपी) के उनकों ने शामिल होने के बाद उन्होंने पार्टी के दो विधायकों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। सरकार के एक निमित्त प्रणाली में बुधवार को कहा गया है, “त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा मंत्री-मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर त्रिपुरा सरकार के मुख्य विधयक तीन जुलाई को अपराह्न देढ़ बजे दरबार लॉन में आकों उपस्थिति की अपील करते हैं।”

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अगरतला में राजभवन में राज्यपाल एन. इंद्रकुल रही से मुलाकात की थी। हालांकि, बुधवार को प्रधारियों के साथों के जवाब में उन्होंने समीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार पर बोलने से इनकार कर दिया था। अभी साहा 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं जबकि एक पद अब भी रिक्त है। इस 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत भाजपा के आठ सदस्य हैं जबकि टीएमपी के दो मंत्री और विपुल्स प्रैट औफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) का एक सदस्य है।

केंद्र का केरल के प्रति नकारात्मक रुख

बरकरार : मुख्यमंत्री

तिरुअनंतपुरम्, एजेंसी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का केरल के प्रति नकारात्मक रुख खारी है और उसने ओणम त्योहार के लिए अतिरिक्त चावल आवंटन की राज्य की मांग को खारिज किया है। मुख्यमंत्री ने सोनीभूषित मंत्र फेसबुक पर एक “पोर्टर” साझा कर सभी राजनीतिक दलों से एकटॉट होकर केंद्र सरकार के कथित केरल विरोधी रुख का विरोध करने का आहान किया है। उन्होंने कहा कि केरल की मांग है तिपेर-प्राथमिकता वाले परिवर्तों को प्रति कार्ड पाच किलोग्राम चावल 800 रुपये की दर से उपलब्ध कराया जाए, जो वर्तमान में राज्य को अतिरिक्त आवंटन के रूप में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप-जैसे विशेष अवसरों के दौरान बाजार में चावल की कीमत को बढ़ने से रोकने के लिए गैर-प्राथमिकता वाले वर्गों को व्यापारियों को अतिरिक्त चावल आवंटन की मांग की है। उन्होंने कहा, गैर प्राथमिकता वाले वर्गों को गैर का आवंटन बहाल करने की मांग उत्तराई गई लोगों की मदद के लिए है। ये मांग अमालोगों की मदद के लिए हैं। इस संबंध में दलगत राजनीति से ऊर ऊर उठकर एकजूट विरोध किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार की केरल विरोधी नीति को दुरुस्त करने के लिए लोगों का विरोध जरूरी है। इसके लिए हमें एकजूट होना होगा।

लाउडस्पीकर बैन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मर्जिदों की कमेटी

मुवर्र, एजेंसी। महाराष्ट्र में मर्जिदों में जनन के लिए लगाए गए लोगों की मदद के लिए है। इस संबंध में दलगत राजनीति से ऊर ऊर उठकर एकजूट विरोध किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार की केरल विरोधी नीति को निर्दृश्य करने के लिए लोगों का विरोध जरूरी है। इसके लिए हमें एकजूट होना होगा।

लाउडस्पीकर बैन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मर्जिदों की कमेटी

मुवर्र, एजेंसी। महाराष्ट्र में मर्जिदों में जनन के लिए लगाए गए लोगों की मदद के लिए है। इस संबंध में दलगत राजनीति से ऊर ऊर उठकर एकजूट विरोध किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार की केरल विरोधी नीति को निर्दृश्य करने के लिए लोगों का विरोध जरूरी है। इसके लिए हमें एकजूट होना होगा।

खेल महासंघों पर नकेल कसने की तैयारी, मॉनसून सत्र में विधेयक लारही सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। खेल महासंघों में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार संसद के आगामी मौसूल सत्र में राज्यीय खेल प्रशासन विधेयक पैश करने की तैयारी में है। यह विधेयक देश में पहली बार एक खेल नियमक संस्था के गठन का प्रावधान करता है, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेल संगठनों के कामकाज की नियंत्रण को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। सरकार के एक निमित्त प्रणाली पर मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा गया है, “त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा मंत्री-विधेयों के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर त्रिपुरा सरकार के मुख्य विधयक तीन जुलाई को अपराह्न देढ़ बजे दरबार लॉन में आकों उपस्थिति की अपील करते हैं।”

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विधेयक के वित्तीय खेल नियमक संस्था को ऋक्षहृषि के दायरे में लाने और एथलीट आयोग व अपीलीय खेल न्यायाधिकरण बनाने का प्रावधान है। मंत्रालय विधेयक के वित्तीय खेल महासंघों को मान्यता देना और उनके प्रशासन, नैतिकता एवं वित्तीय मामलों में नियंत्रण करना होगा।

2. एथलीट आयोग और अपीलीय खेल न्यायाधिकरण :

1. भारतीय खेल नियामक संस्था : यह पांच सदस्यीय नियंत्रण विधायी होगा, जिसकी अध्यक्षता खेल सचिव करेगा।



इसमें एक खेल रल पुस्कार विजेता और एक द्वितीय खेल विधेयक के दायरे में आएंगे।

3. आरटीआई के दायरे में आएंगे खेल महासंघ :

इसके कार्य सभी अपीलीय खेल विधेयक के वित्तीय खेल महासंघों को ऋक्षहृषि अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। हालांकि, कछु संसदीकरणशील जनकारी जैसे कि टीम चयन, खिलाड़ियों के प्रदर्शन, चोट, और चिकित्सा रिकॉर्ड को ऋक्षहृषि के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस कदम का उद्देश्य खेल संगठनों में जनता की भागीदारी और जवाबदेही को बढ़ाना है।

अनेक दोषों के बावजूद भी विशेषज्ञों का वित्तीय खेल महासंघ को मान्यता देना और उनके प्रशासन के लिए एक वैधानिक ढांचा तैयार करने की जवाबदी की गई है। इसी नीति के तहत खेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विधेयक को अब संसद में लाया जाएगा।

विधेयक के 3 प्रमुख प्रावधान

1. भारतीय खेल नियामक संस्था :

यह पांच सदस्यीय नियंत्रण विधायी होगा, जिसकी अध्यक्षता खेल सचिव करेगा।

राजनीतिक विधेयक के चलते वह विधेयक संसद में नई पहुंच सका। संसद का मौसूल सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसमें 23 दिन की अवधि में कई महत्वपूर्ण विधायी एंडेंडों पर चर्चा होगी। इस सत्र में राज्यीय खेल प्रशासन विधेयक के अलावा, वित्त विधेयक, भारतीय वायरान विधेयक 2024, बॉयलर्स विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, और बर्ब (संवर्धन और विकास) विधेयक जैसे अन्य प्रमुख विधेयक भी पेश किए जाएंगे। इसके अलावा, सत्र में ऑपरेशन सिद्धांत जैसे गांधी रुपरेशन से खारिज करते हुए विधेयक के मूल्यांकन के बावजूद विधेयक के वित्तीय खेल महासंघों को ऋक्षहृषि अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। हालांकि, कॉफी संवर्धनशील जनकारी जैसे कि टीम चयन, खिलाड़ियों के प्रदर्शन, चोट, और चिकित्सा रिकॉर्ड को ऋक्षहृषि के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस कदम का उद्देश्य खेल संगठनों में जनता की भागीदारी और जवाबदेही को बढ़ाना है।

अनेक दोषों के बावजूद भी विशेषज्ञों का वित्तीय खेल महासंघ को मान्यता देना और उनके प्रशासन के लिए एक वैधानिक ढांचा तैयार करने की जवाबदी की गई है। इसी नीति के तहत खेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विधेयक को अब संसद में लाया जाएगा।

विधेयक के 3 प्रमुख प्रावधान

1. भारतीय खेल नियामक संस्था :

यह पांच सदस्यीय नियंत्रण विधायी होगा, जिसकी अध्यक्षता खेल सचिव करेगा।

2. एथलीट आयोग और अपीलीय खेल न्यायाधिकरण :

3. आरटीआई के दायरे में आएंगे खेल महासंघ :

इसके कार्य सभी अपीलीय खेल विधेयक के वित्तीय खेल महासंघों को ऋक्षहृषि अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। हालांकि, कॉफी संवर्धनशील जनकारी जैसे कि टीम चयन, खिलाड़ियों के प्रदर्शन, चोट, और चिकित्सा रिकॉर्ड को ऋक्षहृषि के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस कदम का उद्देश्य खेल संगठनों में जनता की भागीदारी और जवाबदेही को बढ़ाना है।

अनेक दोषों के बावजूद भी विशेषज्ञों का वित्तीय खेल महासंघ को मान्यता देना और उनके प्रशासन के लिए एक वैधानिक ढांचा तैयार करने की जवाबदी की गई है। इसी नीति के तहत खेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विधेयक को अब संसद में लाया जाएगा।

विधेयक के 3 प्रमुख प्रावधान

1. भारतीय खेल नियामक संस्था :

यह पांच सदस्यीय नियंत्रण विधायी होगा, जिसकी अध्यक्षता खेल सचिव करेगा।

2. एथलीट आयोग और अपीलीय खेल न्यायाधिकरण :

जीतू पटवारी पर दर्ज किए गए अपराधिक प्रकरण को शीघ्र निरस्त करवाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन

अपराधिक प्रकरण शीघ्र निरस्त नहीं होने पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता 8 जुलाई को मुंगवली थाना में शिरपती देंगे।

पत्रा। जिला कांग्रेस कमेटी पत्रा के अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा के नेतृत्व में सेकड़ों कांग्रेसियों ने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस महानिवेशक मुख्यालय भौपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि अशोकनगर के मुंगवली थाना अंतर्गत सरपंच के दबाव पुरों के द्वारा दो गरीब युवकों जिनके द्वारा खाड़ीपत्र चारों की मांग की जा रही थी उके साथ मारपीट कर पहले उनकी बाइक छीनी गई फिर मानव मल खिलाकर उहँ अपमानित किया गया, पीड़ियों को न्याय दिलाने के लिए आगे एकांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया गया तथा इस मामले को दबाया जा सके लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा यदि अपराधिक प्रकरण शीघ्र निरस्त नहीं किया गया तो कांग्रेस के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाकर भूत हड्डाल अनिवार्यतालीन के लिए की जाएगी तथा आगामी 8 जुलाई



कोजीतू पटवारी के साथ लाखों की संख्या में कांग्रेसियों के द्वारा अशोकनगर जिले के मुंगवली थाना में शिरपती दी जाएगी, ज्ञापन के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी पत्रा के अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा एवं जिला सह

प्रभारी भूपेंद्र राहुल ने क्या कहा कांग्रेस पार्टी फॉनी मामलों से दबाने वाली नहीं है जनता की लड़ाई हर सास तक लड़ी प्रदेश की जन विरोधी दमनकारी सरकार का विरोध जारी रहेगा और ऐसेराम के अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा एवं जिला सह

में बताया गया है कि यह स्कॉम और गाइडलाइन मई 2025 और जून 2025 में जारी हुई हैं। इसी के साथ मंत्रालय द्वारा 21 मई 2025 को यूटर मैनेजमेंट पॉर्टल भी जारी किया गया है। निर्देशों में बताया है कि सड़क दुर्घटना प्रकरणों में जहां दोषी मोरत्यान के पास वैध त्रृतीय पक्ष वीमा कवरेज के अधीक्षक एवं राज्यालय द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाकर भूत हड्डाल अनिवार्यतालीन के लिए की जाएगी तथा आगामी 8 जुलाई

दिनों की अवधि में प्रति व्यक्ति के लिए एक लाख 50 हजार रुपये तक के उत्तराधीन व्यवस्था है। दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति या उसका परिवार दुर्घटना का विवरण हेल्पलाइन नंबर 112 में दे सकता है।

परिवहन सचिव द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि योजना के लिए किसी अधीक्षकारी को जिम्मेदारी देते हुए इसकी नियमित मॉनीटरिंग जिला स्तर पर की जाए। समस्त अस्पताल के दावों को भूजीरा हिए जाने के 10 दिनों की समयावधि में जिला कलेक्टर्स के अनुमोदन से जिला स्तर पर ही केन्द्र सरकार द्वारा निर्वाचित फण्ड से किया जाएगा। योजना में अस्पताल से दुर्घटना तारीख से अधिकतम 7

दिनों की अवधि में प्रति व्यक्ति के

लाल सिंह आर्य के भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनने पर दी बधाई

पत्रा। कोरी-कोली समाज के गौरव पूर्व विधायक पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश भाजपा महामंत्री, वर्तमान में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नियुक्त किये जाने पर, बुद्धेन्द्रण के प्रसिद्ध कावि, प्रतिष्ठित ख्याति लब्ध साहित्यकार, अधिकारी पत्रकार, समाजसेवी एवं मध्यप्रदेश कोरी-कोली समाज महामंत्री के प्रेस संयोजक तथा समाज के जिले के नेता तमानारायण चिरालया ने श्री आर्य को आवश्यक बधाई देते हुये भाजपा शीर्ष नेतृत्व के प्रति धृदिक आधार व्यक्त किया है।

परिवहन सचिव द्वारा जारी

निर्देशों में कहा गया है कि योजना

के लिए किसी अधीक्षकारी को जिम्मेदारी देते हुए इसकी नियमित मॉनीटरिंग

जिला स्तर पर की जाए। समस्त

संभायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि महत्वपूर्ण योजना की आवश्यकता नियमित मॉनीटरिंग की जाए। जिला कलेक्टर्स को योजना से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश भी परिवहन सचिव द्वारा भेजे गए हैं।

परिवहन सचिव द्वारा जारी

निर्देशों में कहा गया है कि योजना

के लिए किसी अधीक्षकारी को जिम्मेदारी देते हुए इसकी नियमित मॉनीटरिंग

जिला स्तर पर की जाए। समस्त

संभायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि महत्वपूर्ण योजना की आवश्यकता नियमित मॉनीटरिंग की जाए। जिला कलेक्टर्स को योजना से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश भी परिवहन सचिव द्वारा भेजे गए हैं।

परिवहन सचिव द्वारा जारी

निर्देशों में कहा गया है कि योजना

के लिए किसी अधीक्षकारी को जिम्मेदारी देते हुए इसकी नियमित मॉनीटरिंग

जिला स्तर पर की जाए। समस्त

संभायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि महत्वपूर्ण योजना की आवश्यकता नियमित मॉनीटरिंग की जाए। जिला कलेक्टर्स को योजना से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश भी परिवहन सचिव द्वारा भेजे गए हैं।

परिवहन सचिव द्वारा जारी

निर्देशों में कहा गया है कि योजना

के लिए किसी अधीक्षकारी को जिम्मेदारी देते हुए इसकी नियमित मॉनीटरिंग

जिला स्तर पर की जाए। समस्त

संभायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि महत्वपूर्ण योजना की आवश्यकता नियमित मॉनीटरिंग की जाए। जिला कलेक्टर्स को योजना से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश भी परिवहन सचिव द्वारा भेजे गए हैं।

परिवहन सचिव द्वारा जारी

निर्देशों में कहा गया है कि योजना

के लिए किसी अधीक्षकारी को जिम्मेदारी देते हुए इसकी नियमित मॉनीटरिंग

जिला स्तर पर की जाए। समस्त

संभायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि महत्वपूर्ण योजना की आवश्यकता नियमित मॉनीटरिंग की जाए। जिला कलेक्टर्स को योजना से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश भी परिवहन सचिव द्वारा भेजे गए हैं।

परिवहन सचिव द्वारा जारी

निर्देशों में कहा गया है कि योजना

के लिए किसी अधीक्षकारी को जिम्मेदारी देते हुए इसकी नियमित मॉनीटरिंग

जिला स्तर पर की जाए। समस्त

संभायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि महत्वपूर्ण योजना की आवश्यकता नियमित मॉनीटरिंग की जाए। जिला कलेक्टर्स को योजना से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश भी परिवहन सचिव द्वारा भेजे गए हैं।

परिवहन सचिव द्वारा जारी

निर्देशों में कहा गया है कि योजना

के लिए किसी अधीक्षकारी को जिम्मेदारी देते हुए इसकी नियमित मॉनीटरिंग

जिला स्तर पर की जाए। समस्त

संभायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि महत्वपूर्ण योजना की आवश्यकता नियमित मॉनीटरिंग की जाए। जिला कलेक्टर्स को योजना से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश भी परिवहन सचिव द्वारा भेजे गए हैं।

परिवहन सचिव द्वारा जारी

निर्देशों में कहा गया है कि योजना

के लिए किसी अधीक्षकारी को जिम्मेदारी देते हुए इसकी नियमित मॉनीटरिंग

जिला स्तर पर की जाए। समस्त

संभायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि महत्वपूर्ण योजना की आवश्यकता नियमित मॉनीटरिंग की जाए। जिला कलेक्टर्स को योजना से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश भी परिवहन सचिव द्वारा भेजे गए हैं।



वैद्यक संगठन यात्री पर्यावरण संस्करण के तहत ज्ञापन करने के बारे में जिला संसदीय समिति ने एक विवरण दिया है।

वैद्यक संगठन यात्री पर्यावरण संस्करण के तहत ज्ञापन करने के बारे में जिला संसदीय समिति ने एक विवरण दिया है।

वैद्यक संगठन यात्री पर्यावरण संस्करण के तहत ज्ञापन करने के बारे में जिला संसदीय समिति ने एक विवरण दिया है।

वैद्यक संगठन यात्री पर्यावरण संस्करण के तहत ज्ञापन करने के बारे में जिला संसदीय समिति ने एक विवरण दिया ह

